

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 9185/2022 M/s Maihar Traders, Bunglow No. 30, Phase-02, Shree Golden City Jatkhedi, Hoshangabad Road, Huzur, Dist. Bhopal, MP - 462026, Prior Environment Clearance for Limestone, Dolomite and Reject Stone Mine in an area of 26.224 ha. (3.0 Lac Tonne per annum) (Khasra No. 196/1, 196/2, 197, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) EIA Consultant – Uplinka**

This is case of Limestone, Dolomite and Reject Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 196/1, 196/2, 197, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) 26.224 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट,

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। चूंकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खनिज लाईम स्टोन एवं डोलोमाइट (लीज एरिया 26.224 हे.) का होने के कारण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। इसी प्रकार खदान के पूर्वी क्षेत्र में नहर के समान कोई संरचना दिख रही है अतः इसकी वास्तविक स्थिति का विवरण मय संरक्षण योजना के ईआईए के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान में एक गड़ढ़ा दिखा रहा है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यहाँ पूर्व में अवैध खनन किया गया है, अतः समिति ने निदेशित किया कि तत्संबंध में खनिज अधिकारी का प्रमाण पत्र ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
2. खदान के पूर्वी क्षेत्र में नहर के समान कोई संरचना दिख रही है अतः इसकी वास्तविक स्थिति का विवरण मय फोटोग्राफ एवं संरक्षण योजना के ईआईए के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे।
4. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. खदान के पूर्वी भाग से नहर निकल रही है, अतः उसका संरक्षण योजना एवं आवश्यक सेट-बैक छोड़ते हुए ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
8. लीज क्षेत्र से एक एच.टी. लाइन निकल रही है, अतः 50-50 मीटर का सेट-बैक छोड़ते हुए संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
9. खदान में एक गड़ढ़ा दिखा रहा है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यहाँ पूर्व में अवैध खनन किया गया है, अतः समिति ने निदेशित किया कि तत्संबंध में खनिज अधिकारी का प्रमाण पत्र ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये।

**575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 मई 2022**

**2. Case No 9184/2022 M/s Hukamchand Stone Lime Company, Nat Bolt House, Nadi Par, Dist. Katni, MP, Prior Environment Clearance for Limestone Mine in an area of 4.046 ha. (Limestone - 23760 Tonne per annum, OB - 15840 Tonne per annum) (Khasra No. 17, 18/2), Village - Bhatoora, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Limestone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 17, 18/2), Village - Bhatoora, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) 4.046 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। चूंकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन लाईम स्टोन (लीज एरिया 4.046 हे.) का होने के कारण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। इसी प्रकार खदान के दक्षिण क्षेत्र में 260 मीटर पर आबादी है अतः उसकी संरक्षण योजना के ईआईए के साथ प्रस्तुत की जाये। एकल प्रमाण पत्र अनुसार संभागायुक्त की अनुशंसा एवं वन मण्डलाधिकारी की एनओसी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दिनांक 17/01/17 को संभागायुक्त की बैठक में अनुमति मिल चुकी है, उक्त संभागायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यवाही विवरण एवं वन मण्डलाधिकारी की एनओसी की प्रति प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान 1992 से 2012 के मध्य उत्पादनरत रही तथा 2012 में लीज एक्सटेंशन के समय मण्डलाधिकारी ने वन क्षेत्र संबंधी जानकारी चाही गई थी जिसके पालन में उनके द्वारा दिनांक 17/01/17 को आयोजित संभागायुक्त की बैठक में सशर्त अनुमति प्राप्त की गई है जिसके अनुसार वन सीमा की ओर से लीज के अंदर 50 मीटर की दूरी तक उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
2. दक्षिण क्षेत्र में 260 मीटर पर आबादी है अतः उसकी संरक्षण योजना के ईआईए के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. उत्खनन क्षेत्र पहाड़ के तलहटी पर है, अतः सतही जल का केचमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
8. एकल प्रमाण पत्र अनुसार संभागायुक्त की अनुशंसा एवं वन मण्डलाधिकारी की एनओसी उपलब्ध नहीं है । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दिनांक 17/01/17 को संभागायुक्त की बैठक में अनुमति मिल चुकी है, उक्त संभागायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यवाही विवरण एवं वन मण्डलाधिकारी की एनओसी की प्रति ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. संभागायुक्त अनुशंसा अनुसार वन सीमा की ओर से लीज के अंदर 50 मीटर की दूरी उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, इस संबंध में 50 मीटर का सेट-बैक दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।

### **3. Case No 9187/2022 Director, M/s Marwadi Sales Pvt. Ltd, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.750 ha. (1,20,000 Cum per annum) (Khasra No. 584), Village - Tikari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 584), Village - Tikari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 2.750 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 4425 दिनांक 02/09/2019 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 12.400 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 50 मीटर पर आबादी है अतः 150 मीटर का सेट बेक नॉन माईनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना होगा तथा उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जानी होगी । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह देखा गया कि यदि आबादी से 200 मीटर का नॉन माईनिंग जोन (लीज क्षेत्र में 150 मीटर का नॉन माईनिंग जोन) छोड़ा जाता है तो खनन हेतु बहुत कम क्षेत्र (लगभग 0.60 हे.) ही उपलब्ध होता है अतः परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करले कि इतने कम क्षेत्र में से वांछित उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकती है अथवा नहीं। तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा तथा उस स्थिति में लीज के अंदर से 50 मीटर का नॉन माईनिंग जोन छोड़ा जावेगा तथा इस स्थिति में वांछित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है । समिति ने आवेदन के संलग्न खनन योजना का अवलोकन किया तो पाया कि आवेदन के साथ संलग्न अनुमोदित खनन योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित की गई है । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वे पुनरीक्षित खनन योजना बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर चुके हैं तथा ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित खनन योजना अपलोड कर देंगे । चूंकि प्रस्तावित खनन क्षेत्र पहाड़ के ऊपर स्थित है अतः समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.आई.ए. में वैज्ञानिक आधार पर यह सिद्ध किया जाये कि क्या रॉक ब्रेकर के माध्यम से इस पहाड़ पर खनन किया जा सकता है यदि हां तो किस गहराई तक । अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान पहाड़ी के सबसे ऊँचे भाग पर स्थित है, अतः मिरनल इवेक्वेशन प्लान ग्रेडियेंट के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 50 मीटर पर आबादी है अतः 150 मीटर का सेट बेक नॉन माईनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना होगा तथा उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जानी होगी ।
2. यदि आबादी से 200 मीटर का नॉन माईनिंग जोन (लीज क्षेत्र में 150 मीटर का नॉन माईनिंग जोन) छोड़ा जाता है तो खनन हेतु बहुत कम क्षेत्र (लगभग 0.60 हे.) ही उपलब्ध होता है अतः परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करले कि इतने कम उपलब्ध क्षेत्र में से वांछित उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकती है अथवा नहीं ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित बताया अतः पुनरीक्षित खनन योजना बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के द्वारा ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र पहाड़ के ऊपर स्थित है अतः ई.आई.ए. में वैज्ञानिक आधार पर यह सिद्ध किया जाये कि क्या रॉक ब्रेकर के माध्यम से इस पहाड़ पर खनन किया जा सकता है यदि हां तो किस गहराई तक ।

**575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 मई 2022**

5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
7. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

**4. Case No 9183/2022 Shri Jakiuddin Kaji, Owner, Juna Bazar, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 172), Village - Malya, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam (MP) EIA Consultant : Apex Mintech Udaypur (Rj.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 172), Village - Malya, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 865 दिनांक 10/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 9.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान पश्चिमी भाग खुदा हुआ है जहाँ पर गूगल इमेज अनुसार 2013 से खनन कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको लीज इसी स्थिति में मिली है तथा पूर्व निकाले गये खनिज के विवरण माईन प्लान में दर्ज किये गये हैं तथा सरफेस मैप पर गड़ढा दिखाया गया है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है । अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्वेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**5. Case No 9186/2022 Shri Wasim Khan, Owner, Dargah Mohalla, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (19950 Cum per annum) (Khasra No. 385/2/2), Village - Jeevangarh, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam (MP) EIA Consultant: Congnizance Research India (P) Ltd., Noida (UP).**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 385/2/2), Village - Jeevangarh, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 763 दिनांक 27/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 17.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 165 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्तर-पूर्व दिशा में ही 205 मीटर पर मंदिर है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान खुदी हुई है जहाँ पर गूगल इमेज अनुसार 2011 से खनन कार्य किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

कि उनको लीज इसी स्थिति में मिली है तथा पूर्व निकाले गये खनिज के विवरण माईन प्लान में दर्ज किये गये हैं तथा सरफेस मेप पर पुराना पिट दिखाया गया है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 165 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्तर-पूर्व दिशा में ही 205 मीटर पर मंदिर है । अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**6. Case No 9188/2022 M/s J.P.Mines and Minerals, Partner, Shri Pawan Kumar Singhal, 704, Satyam Tower, City Center, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.390 ha. (75852 Cum per annum) (Khasra No. 1, 4, 7, 52), Village - Bilara, Tehsil - Tansen, Dist. Gwalior (MP) EIA Consultant: Congnizance Research India (P) Ltd., Noida (UP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 4, 7, 52), Village - Bilara, Tehsil - Gwalior, Dist. Gwalior (MP) 3.390 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू-3 दिनांक 30/03/22 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 90 मीटर पर नहर है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण



**575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 मई 2022**

में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 90 मीटर पर नहर है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
4. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. शासकीय भूमि (यदि हो तो) का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

**7. Case No 9190/2022 Shri Pankaj Joshi, 2/14, Jharenshtar Complex, Jawahar Chowk, New Market, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (25080 Cum per annum) (Khasra No. 20/1 Part), Village - Leelakhedi, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) EIA Consultant: Cognizance Research India (P) Ltd., Noida (UP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 20/1 Part), Village - Leelakhedi, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 30/05/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**8. Case No 9182/2022 Shri Govind Prasad Paroha, Owner, Lamtara, Dist. Panna, MP - 488448 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 3.0 ha. (30000 Cum per annum) (Khasra No. 1381/1), Village - Dungargawan Tehsil - Shahnagar, Dist. Panna (MP)**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1381/1), Village - Dungargawan Tehsil -

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

Shahnagar, Dist. Panna (MP) 3.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 489 दिनांक 26/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 160 मीटर तथा उत्तर दिशा में 145 मीटर पर पर जलीय निकाय स्थित है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर आबादी है। परीक्षण में दौरान पाया गया कि लीज एरिया के अंदर से एक कच्ची रोड़ निकल रही है, जिस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह शासकीय भूमि पर स्वीकृत मुरुम खदान है जिमसे ब्लैस्टिंग प्रस्तावित नहीं है। पूर्व में इस क्षेत्र से पगडंडी थी जो अब उपयोग नहीं आती है फिर भी हम इस क्षेत्र को नॉन माईनिंग जोन के रूप में छोड़ रहे हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरुम का है अतः ब्लैस्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा जलीय निकाय की सुरक्षा हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये हैं तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी./वृक्षारोपण/सीईआर योजना।
- ✓ लीज एरिया के अंदर से एक कच्ची रोड़ निकल रही है, अतः सेड-बैंक नॉन माईनिंग क्षेत्र दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 30/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम – 30,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.79 लाख प्रति वर्ष।

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.03 लाख :-

सी. ई. आर. गतिविधि					
साल	संस्था का नाम	उपकरण सामग्री	कंपनी	संख्या	राशि
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परसबरा (ग्राम डुगरगवां)	ECG Machine With Report	Medonics	01	50,000
		Radiant Warmer	BLT Monitoring Company	01	35,000
		Refrigerator	LG	01	15,000
		Shadowless led Lamp for OT	Surgicoim	01	18,000
		Split A.C. 1.5 Ton	Godrej	01	35,000
		Stretcher	Cosmocare	02	30,000
		Wheel Chair	Arcatron	02	20,000
		योग			2,03,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, पीपल, सिस्सु, बरगद, चिरोल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
गैर खनन क्षेत्र	नीम, पीपल, सिस्सु, बरगद, चिरोल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	नीम, करंज, आम, सिस्सु, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, अमरुद, पपीता, नींबू, हर्षा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500
योग		3600

**575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 मई 2022**

**9. Case No 9189/2022 Shri Gourav Choudhary Owner, 26 Pilpiya Hana, Tilak Nagar Road, Dist. Indore, MP- 452001, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (20,000 Cum per annum) (Khasra No. 2257/2), Village - Datoda, Tehsil - Mhow, Dist. Indore (MP)**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2257/2), Village - Datoda, Tehsil - Mhow, Dist. Indore (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 983 दिनांक 27/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 100 मीटर पर मौसमी जलीय निकाय स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलीय निकाय के कारण गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये हैं तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरुम का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा लीज में विद्यमान 09-10 पेड़ हैं जिसमें से कोई पेड़ काटा नहीं जायेगा तथा लीज के दक्षिणी-पूर्वी भाग में पेड़ों को बचाने के लिए नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ा गया है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र कि उत्खनन हेतु लीज में विद्यमान पेड़ों का काटा नहीं जायेगा तथा उस क्षेत्र को नॉन माईनिंग जोन घोषित किया जायेगा।
- ✓ नॉन माईनिंग क्षेत्र (लीज के दक्षिणी-पूर्वी भाग) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी./वृक्षारोपण/सीईआर योजना।
- ✓ उत्खनन कार्य हेतु आवश्यक जलापूर्ति की अनुमति।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 30/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मरुम-20,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.57 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.92 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 03.00 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम दतोदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 फोल्डेबल व्हील चेयर्स उपलब्ध कराई जाएंगी।	15,000/-
ग्राम दतोदा के आंगनवाड़ी केंद्र में भोजन बनाने, खाने एवं रखने हेतु बर्तन एवं बच्चों के लिए खिलोने उपलब्ध करवाए जाएंगे।	15,00/-
<b>योग</b>	<b>30,000 / -</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2430 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	1220
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, करंज, बरगद, चिरोल, नीम, सिस्सू आदि।	280
3	ग्राम दतोदा के प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल करंज, आवला आदि।	50
4.	ग्राम दतोदा के शासकीय विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, कचनार, सप्तपर्णी, नीम, करंज आदि।	150
5.	ग्राम के ग्रामीणों में वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, जामुन, अमरुद, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल आदि।	730
<b>कुल वृक्षारोपण</b>			<b>2430</b>

**575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 मई 2022**

**10. Case No 9191/2022 Shri Ram Kalesh, Owner, Village - Kulgawan Madaiyan, Tehsil - Gunnor, Dist. Panna, MP - 488333, Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.670 ha. (5000 Cum per annum) (Khasra No. 30, 31, 32, 33), Village - Jaithupura, Tehsil - Pawai, Dist. Panna (MP)**

This is case of Flag Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 30, 31, 32, 33), Village - Jaithupura, Tehsil - Pawai, Dist. Panna (MP) 1.670 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 543 दिनांक 05/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

एकल प्रमाण-पत्र अनुसार प्रश्नाधीन खदान 250 के अंदर है। इस संबंध में संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04/02/22 के प्रकरण क्रमांक-2 समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र ग्राम जैतपुरा तहसील पर्वी जिला पन्ना के शासकीय भूमि खसरा नं० 30, 31, 32, 33 में से रकबा 2.670 हेक्टेयर वन सीमा से 50 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन पट्टा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। आवेदक वन सीमा के ओर 50 मीटर तक ग्रीन बेल्ट (बफर जोन) स्थापित करेगा तथा कोई खनन कार्य नहीं करेगा। पट्टेदार स्वीकृत क्षेत्र पर वन मण्डलाधिकार के निर्देशन में तार फेंसिंग करेगा। उत्खनन पट्टाधारी वन भूमि के अंदर ओवर वर्डन नहीं डालेगा, स्वीकृत लीज में ही ओवर वर्डन डाला जाएगा एवं वन भूमि से आवागमन नहीं करेगा। आवेदक लीज क्षेत्र के चारों ओर राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं वन विभाग के अमले की उपस्थिति में सीमांकन कराकर सीमेंट कांकीट के पक्के मुनारे बनायेगा एवं खदान स्वीकृति से संबंधी विवरणी बोर्ड स्थापित करेगा। स्वीकृत क्षेत्र में वन सीमा की ओर सी.सी. टी.वी. कैमरा लगायेगा व कम से कम 15 दिन की रिकार्डिंग रखेगा। अनुमोदित खनन योजना अनुसार कार्य किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में 07 – 10 पेड़ लगे हैं जिनको काटा नहीं जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फ्लेग स्टोन माइनिंग का है जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा उत्पादन क्षमता मात्र 5,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष है अतः खनन क्षेत्र में लगे हुए पेड़ों के चारों ओर एक मीटर का घेरा छोड़ कर खनन कार्य किया जायेगा जिससे पेड़ न काटने पड़े। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि जो गड्ढे आवेदित खनन् क्षेत्र में दिख रहे हैं, के संदर्भ में उनके द्वारा खनिज अधिकारी से जानकारी पत्र क्रमांक 657 दिनांक 25/05/22 के माध्यम से प्राप्त की गई है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि खनन् क्षेत्र में जो गड्ढे दिख रहे हैं, वे पूर्व के हैं तथा 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि एकल प्रमाण-पत्र के अनुसार खदान क्षेत्र वन क्षेत्र से 250 मीटर की दूरी के अंदर है तथा संभागीय आयुक्त समिति बैठक दिनांक 08/02/22 के अनुसार वन क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी छोड़कर खदान स्वीकृति की अनुशंसा की गई है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ संभागीय आयुक्त समिति बैठक दिनांक 08/02/22 में की गई के अनुशंसाओं एवं शर्तों का पालन हेतु परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सीईआर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 30/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता प्लेग स्टोन – 5,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. संभागीय आयुक्त समिति बैठक दिनांक 08/02/22 में की गई के अनुशंसाओं एवं शर्तों का पालन किया जाये ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.08 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम जैतपुरा के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व बच्चों के खेलने के लिए लकड़ी के खिलौने तथा बची हुई राशि से 1वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा ।	50,000 /—
योग	50,000 /—

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2010 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू नीम, बबूल, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	700
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	310
3	वन सीमा की ओर से 50 मीटर तक (बफर जोन)	शीशम, अमलतास, खमैर, नीम, करंज, चिरौल अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
कुल वृक्षारोपण			2010

**11. Case No 9192/2022 Shri Gordhan Bhaydiy, Owner, Village - Partali, Tehsil - Ranapur, Dist. Jhabua, MP - 457993, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.80 ha. (9975 Cum per annum) (Khasra No. 52), Village - Partali, Tehsil - Ranapur, Dist. Jhabua (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 52), Village - Partali, Tehsil - Ranapur, Dist. Jhabua (MP) 1.80 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 420 दिनांक 05/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।



## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 50 मीटर पर पक्का रोड़ व उत्तर एवं पश्चिम दिशा में कच्चा रोड़ क्रमशः 10 मीटर एवं 12 मीटर पर है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्खनन हेतु लीज में विद्यमान 01 पेड़ जो कि नीम प्रजाति का है, को काटा नहीं जायेगा। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सीईआर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 30/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 9,975 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 06.17 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम परताली के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व बच्चों के खेलने के लिए लकड़ी के खिलौने तथा बची हुई राशि से 1वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा ।	60,000 / -
योग	60,000 / -

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, कस्टार, बरगद, खमैर, चिरौल, पीपल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	800

**575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 मई 2022**

2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम उचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, अमलतास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
3	परताली ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, नीम, आम, अमरुद अन्य फलदार प्रजातियाँ।	1080
4.	शासकीय विद्यालय परताली में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर आदि (ट्री-गार्ड के साथ यदि बाउण्ड्रीवाल नहीं है तो)	20
<b>कुल वृक्षारोपण</b>			<b>2200</b>

**12. Case No 9193/2022 Shri Jitendra Yadav, Owner, A-2, Mandakini Block, Kevihgar Line 1, Batalian, Dist. Indore, MP - 453111 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.20 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 178/228/1), Village – Alwasa Tehsil Mhow, Dist. Indore (MP)**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 178/228/1), Village - Alwasa, Tehsil - Hatod, Dist. Indore (MP) 1.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 122 दिनांक 10/01/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई (01 उत्खनन पट्टा स्वीकृत जो मा. न्यायालय के आदेश से शिथिल अवस्था में) खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर के अंदर एक उत्खननपट्टा स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय के आदेश पालन में शिथिल अवस्था में है। समिति को उपरोक्त एकल प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव इस खदान पर भी लागू है या नहीं। अतः इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक से मा. उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के बारे में जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी उनके पास इस संदर्भ में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः जानकारी प्रदाय करने हेतु 10 दिन का समय दिया जाये। अतः समिति की अनुशंसा है कि मा.

**575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 मई 2022**

उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण की अद्यतन वस्तुस्थिति से 10 दिनों में अगवत कराया जाये, तत्पश्चात् प्रकरण विचार किया जावेगा ।

**13. Case No 9194/2022 Shri Shailendra Singh Owner, Village – Sagoni Guru, Tehsil – Jaisinagar, Dist. Sagar, MP - 470120, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (14,022 Cum per annum) (Khasra No. 236/1, 236/2), Village - Sattaadhana, Tehsil - Jeseennagar, Dist. Sagar (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 236/1, 236/2), Village - Sattaadhana, Tehsil - Jeseennagar, Dist. Sagar (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 739 दिनांक 21/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 225 मीटर पर पक्का रोड़ है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 30/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन-14,022 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 08.02 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.57 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.03 लाख :-

**575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 मई 2022**

सी. ई. आर. गतिविधि					
साल	संस्था का नाम	उपकरण सामग्री	कंपनी	संख्या	राशि
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सत्ताढांना	Split A.C. 1.5 Ton	Gordrej	01	35,000
		Radiant Warmer	BLT Monitoring Company	01	35,000
		Refrigerator	LG	01	15,000
		Crash Cart	Inline	01	18,000
		Total			1,03,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, पीपल, सिस्सु, बरगद, चिरोल, खामेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम उचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, आम, सिस्सु, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, अमरुद, पपीता, नींबू, हर्रा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
योग		1200

**14. Case No 8624/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.082 ha. (70000 cum per annum) (Khasra No. 1214, 1215), Village - Pasan, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Noida (U.P.)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1214, 1215), Village - Pasan, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 6.082 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

The case was presented by Consultant Shri Amar Singh Yadav behalf of PP. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Janpad Panchyat NOC, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office (Ekal Praman-Patra) letter No. 1105 dated 04/06/2021 has reported that there are no more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 513वीं दिनांक 08/09/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

प्रकरण आज दिनांक 30/05/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है किंतु परियोजना प्रस्तावक और न ही उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

### **15.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला राजगढ़ (म.प्र.)**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 600 दिनांक 26/05/22 के माध्यम से राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में प्रस्तावित की गई ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ म.प्र. ने पत्र 479 दिनांक 26/05/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 30 दिवस की अवधि हेतु अपलोड किया गया था तथा 21 दिन के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए । इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 05/4/22 को किया गया ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :-

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

- ✓ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 600 दिनांक 26/05/22 के माध्यम से राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारीयों समाहित की गई है बिंदु क्रमांक-26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोड़कर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजगढ़ जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी नहीं दी गई है तथा पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ भी प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जब भी अद्यतन किया जाये उपरोक्त जानकारीयों को समाहित किया जाये ।
- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 25 पर अंकित है कि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में रेत की रॉयल्टी टेबल में रेत का उत्पादन “नॉट एप्लीकेवल” दर्शाया गया है परंतु शासकीय राजस्व इन वर्षों में दर्शाया गया है जिस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाना चाहिए ।
- ✓ इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 68-69 टेबिल क्रमांक-21 में खनिज रेत हेतु “माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल” (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोर्टेंशियल) लीजवार विवरण (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है ।
- ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को-आर्डिनेट के अनुसार डिजिटालाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेरेबल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

### **16.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला झाबुआ (रेत खदान को छोड़कर) (म.प्र.)**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 596 दिनांक 26/05/22 के माध्यम से झाबुआ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में प्रस्तावित की गई ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ म.प्र. ने पत्र 599 दिनांक 24/05/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 30 दिवस की अवधि हेतु अपलोड किया गया था तथा 21 दिन के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए । इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 20/4/22 को किया गया ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में झाबुआ जिले श्री धमेन्द्र चौहान, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खदान को छोड़कर) पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :-

- ✓ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 596 दिनांक 20/05/22 के माध्यम से झाबुआ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है बिंदु क्रमांक-26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत खदान को छोड़कर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि झाबुआ जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी नहीं दी गई है तथा पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जब भी अद्यतन किया जाये उपरोक्त जानकारियों को समाहित किया जाये ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि झाबुआ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खदान को छोड़कर) पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति ( बैठक दिनांक 20/04/22 में) द्वारा किया जा चुका है । अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये ।

### **17.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला भिण्ड (म.प्र.) ।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 519 दिनांक 20/05/22 के माध्यम से भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 26/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में प्रस्तावित की गई ।

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड म.प्र. ने पत्र 5608 दिनांक 19/05/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 30 दिवस की अवधि हेतु अपलोड किया गया था तथा प्राप्त आपत्ति/सुझाव को समिति द्वारा अवलोकन एवं निराकरण कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया गया । इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में भिण्ड जिले श्री राकेश देशमुख, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :-

- ✓ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 519 दिनांक 20/05/22 के माध्यम से भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारी समाहित की गई है बिंदु क्रमांक-26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोड़कर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भिण्ड जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जब भी अद्यतन किया जाये उपरोक्त जानकारियों को समाहित किया जाये ।
- ✓ चर्चा के दौरान उपस्थित श्री राकेश देशमुख, प्रभारी खनिज अधिकारी को बताया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 92-94 टेबिल क्रमांक-17 में खनिज रेत हेतु “माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल” (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) लीजवार नहीं दिया गया है जिसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि यह जानकारी उनके पास उपलब्ध है तथा वे “माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल” (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) का लीजवार विवरण प्रस्तुत कर देंगे, अतः भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन करने का अनुरोध है ।
- ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को-आर्डिनेट के अनुसार डिजिटार्इज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।



**575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 मई 2022**

कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा ने पत्र क्रमांक 5651/1/2022 दिनांक 30/5/22 के माध्यम से “माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल” (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) लीजवार विवरण की जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति ( बैठक दिनांक 18/05/22 में) द्वारा किया जा चुका है तथा कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा ने पत्र क्रमांक 5651/1/2022 दिनांक 30/5/22 के माध्यम से “माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल” (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है । अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये ।

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

### **Annexure- 'A'**

#### **Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'B'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - i. Minable Potential of sand mine.
  - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
  31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।  
**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

### Annexure- 'C'

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
  15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
  16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
  18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
  19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
  20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
  21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
  22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - o. Minalable Potential of sand mine.
    - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
  27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.



## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केंचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साइड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

## 575वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.